SHRI SHIVRAJ V. PAUL: Sir, I move :

That the Bill as amended be passed.

The question was put and the motion was adopted

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the twenty-third report of the Department-Related Standing Committee on Information Technology

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, on behalf of my colleague I lay a copy of the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the Twenty-third Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Information Technology.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): Shri Dara Singh. Not here. Shrimati Shobhana Bhartia. Not here. Shri S.P.M. Syed Khan. Not here. Shri Datta Meghe. Not here. Shri Ali Anwar.

Need to protect banarsi saree industry from closure

श्री अली अनवर (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे हजार साल पुराने बनारसी साड़ी उद्योग पर चीन की बुरी नज़र लग गई हैं । छह लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ हिस्सों में फैला बनारसी साड़ी उद्योग इस समय आतंक के साये में हैं । चीनियों ने अपने कई तरह के सस्ते सिल्क को वाराणसी के बाजार में झोक दिया हैं । अब उनका इरादा चीन में बड़े पैमाने पर बनारसी साड़ियों का उत्पादन कराना हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक तरफ चीन ने अपने सस्ते निर्यातों के जरिए यार्न बाजार पर कब्ज़ा कर लिया हैं, दूसरी तरफ रिफॉन, क्रेप और साटिन जैसे सस्ते फैब्रिक को हमारे बाजार मे झोंक रहा हैं । आज बनारसी साड़ी उद्योग पूरी तरह सस्ते चीनी धागे पर निर्भर हैं । चूंकि बाजार पर उनका कब्जा हैं, इसलिए वे धीरे-धीरे कीमते भी बढ़ा रहे हैं ।

इसके परिणामस्वरूप हस्तकरघा क्षेत्र के हजारों बुनकर व्यापार से बाहर हो गए हैं । इस उद्योग में पारंपरिक रूप से जुड़े छह लाख बुनकरों में से तीन लाख बुनकर, रिक्शा चलाने तथा दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं । पिछले दो-तीन सालों में बनारस के सैकड़ो बुनकर

अपना मकान बेचकर दूसरे शहरों में मजदूरी करने चले गए हैं । हाल की में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों का अध्ययन एक ख्याति प्राप्त संस्था द्वारा कराया गया हैं, जिससे बड़े ही खराब हालात सामने आए हैं । बिहार के भागलपुर कस सिल्क उद्योग तो पूरी तरह से चीनी अजगर के पेट में समा गया हैं ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि बनारसी साड़ी उद्योग और भागलपुर के सिल्क उद्योग के पुनर्रुद्धार के लिए वह कारगर कदम उठाए । धन्यवाद ।

मौलाना औबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको इसके साथ वाबस्ता करता हूं । यह बहुत अहम मैटर हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA): Shri Gireesh Kumar Sanghi. Not here. Shri Lalit Kishore Chaturvedi. Not here. Shri B.K. Hariprasad.

Need for reforms in the process of selection in Judicial Services

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, even after five decades of independence and coming into force of the Constitution of India, empowering the SC/ST and the OBC communities, by way of reservation to secure opportunities in the areas of education and employment, there has not been much change, as envisaged by visionaries who framed the Constitution, in the socio-econo/nic status of these downtrodden and oppressed classes.

Despite provision of reservation for SC/ST/OBCs in the UPSC selection process, the Dalit community has come a long way to prove that merit is not the sole virtue of the privileged, by securing more than 50 seats in the UPSC selection during last year. It is, therefore, high time that SC/ST/OBCs are given their rightful share in judicial appointments on merits. Under article 312 of the Constitution, it has been mandated to create an All-India Service for Judicial Service like the IAS, IPS, IFS etc. whereby the process of nomination to the Judiciary presently followed, be done away with.

I urge upon the Centre to initiate action in this direction by enactment of law at the earliest.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member,

.MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): I associate myself with the special mention made by the hon. Member.